LL.B. – 2nd Semester

ECONOMICS (Indian Economics)

Unit – 1 & 2

Scanned with CamScanner

LL.B. Second Semester

Economics-II (Paper-III)

1) **Indian Economy at the time of Independence:**
Colonial Economy, Semi-Feudal Economy, Backward Economy, Stagnant economy, Other salient features, planning exercises in India- National Planning committee , Bombay Plan, people plan, Gandhian Plan , the Planning Commission.

2) **Structure of the Indian Economy:**
Basic features, Natural resources- Land water and forest resources, Broad demographic features- Population size and growth rates, Sex composition, rural- Urban migration, Occupational distribution, Problem of over Population, Population Policy, Infrastructural development, national Income.

3) **Planning in India:** Pg. 414
Objectives, Strategy, Broad achievements and failures, current five years plan objectives, Allocation and targets, New economic reforms-liberalization, Privatization and Globalization, Rationale behind economic reforms, progress of privatization and globalization.

4) **Agriculture:**
Nature and importance, Trends in agriculture production and productivity, Factor determining productivity, Land reforms, New Agriculture Strategy and green revolution, Rural credit, Agriculture marketing.

5) **Industry:**
Industrial development during the planning period, Industrial policy of 1948,1956,1977 and 1991, Industrial licensing policy MRTP Act, FERA and FEMA, Growth and problems of small scale industries, Role of public sector enterprises in India's industrialization.

6) **External Sector:**
Role of foreign trade, Trends in exports and imports, Composition and Direction of India's foreign trade, Balance of payments crisis and the new economic reforms- Export promotion measures and the new trade policies, foreign capital-FDI and Multinational Corporation (MNCs).

7) **Important areas of concern:**
Poverty and inequality, Unemployment, Rising prices, Industrial Relations.

26/3/2020 28/3/2020

Scanned with CamScanner

Moh. Mushir – LL.B. – II nd Sem (5 yr)

UNIT-I [INDIAN ECONOMY AT THE TIME OF INDEPENDENCE

स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था

अंग्रेजों के भारत आने से पहले भारतीय अर्थ-व्यवस्था विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के समान थी। यहाँ कृषि एवं दस्तकारी के कार्यों की प्रमुखता थी तथा गाँव आत्मनिर्भर थे। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति ग्रामीण थी। देश की 90% से अधिक जनसंख्या गाँव में रहती थी और कृषि पर निर्भर करती थी। भारत के रेशमी व सूती वस्त्र विश्व में उत्तम श्रेणी के माने जाते थे। यहाँ पर संगमरमर का कार्य, लकड़ी पर नक्काशी का कार्य, सोने चाँदी के आभूषण व पत्थर पर तराशी कार्य बहुत ही उत्तम किस्म का होता था।

ब्रिटिश शासन ने भारत पर न केवल राज्य किया बल्कि इसको एक उपनिवेश बना दिया। उपनिवेश का अर्थ है कि इस देश को किसी प्रकार की राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं थी तथा आर्थिक गतिविधियों पर ब्रिटिश शासक का नियंत्रण था। भारत पर सन 1757 से 1858 तक ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने तथा इसके बाद 1858 से 1947 तक ब्रिटिश सरकार ने राज्य किया।

स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति का अध्ययन हम निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर कर सकते हैं :-

1. उपनिवेशी अर्थव्यवस्था (Colonial Economics)
2. ~~अर्थ~~ अर्द्ध-सामंतवादी अर्थव्यवस्था (Semi-feudal Economics)
3. पिछड़ी अर्थव्यवस्था (Backward Economics)
4. गतिहीन अर्थव्यवस्था (Staynant Economics)

Scanned with CamScanner

① उपनिवेशी अर्थव्यवस्था :-

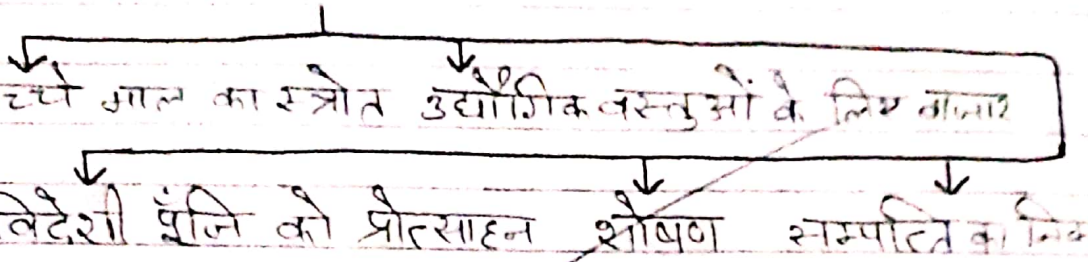

② अर्द्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था :-

अर्थ→ अंग्रेजों ने भारत में आकर अर्द्ध-सामंतवादी अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। इस अर्थव्यवस्था में एक ओर सरकार व दूसरी ओर सामंत थे और दोनों को ही अधिकार इसलिए इसको मिलकर जो अर्थव्यवस्था बनायी उसे अर्द्ध-सामंतवादी अर्थव्यवस्था कहा गया। अंग्रेजों ने जिस अर्द्ध-सामंतवादी अर्थव्यवस्था की शुरूआत कर दी थी वो इस प्रकार थी :-

(i) इस अर्थव्यवस्था में भूमि के मालिकों को किरायदारों (Tenants) में बदल दिया गया। जमीन्दार भूमि का किराया बेतहाशा बढ़ा देते थे।

(ii) इस प्रणाली ने देश में आधा बटाई (Share Cropping) प्रणाली की शुरूआत की।

(iii) जमीनदार किसानों से बेगार लेते थे।

(iv) जमीनदारों को अर्द्ध-न्यायिक राजनैतिक अधिकार (Quasi Judicial Political Power) प्राप्त थे।

(v) उस समय कृषि तकनीक पुरानी थी। कृषि उत्पादन पेट भरने के लिए होता था न कि व्यापार के लिए।

Scanned with CamScanner

अंग्रेजों ने भारत में इस अर्थव्यवस्था को अचानक देश का शोषण किया व किसानो को पनपने नहीं दिया इससे आंतरिक बाजार सीमित हो गया।

(3) पिछड़ी अर्थव्यवस्था :-

अर्थ → जिस देश में गरीबी होती है, पूंजि निर्माण की दर कम होती है, लोगों का जीवन स्तर निम्न होता है वहाँ विकास की दर शून्य होती है तो उस देश की अर्थव्यवस्था को पिछड़ी अर्थव्यवस्था कहते हैं।

अंग्रेजो ने जब भारत को छोड़ा था तो उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई थी जो निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है :-

(i) कम प्रतिव्यक्ति आय (Low Per Capita Income) :-

प्रतिव्यक्ति आय वह पैमाना है जिसके जरिए यह पता चलता है कि किसी देश में एक व्यक्ति की सलाना आमदनी कितनी है साथ ही देश, शहर और क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर और गुणवत्ता का पता चलता है। प्रतिव्यक्ति आय निकालने के लिए देश की कुल आमदनी में कुल जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आय निकाली जा सकती है।

$$\text{प्रति व्यक्ति आय} = \frac{\text{कुल राष्ट्रीय आय}}{\text{जनसंख्या}}$$

$$P.C.I. = \frac{\text{Total National Income}}{\text{Population}}$$

Scanned with CamScanner

② गरीबी और असमानता :-

जब देश की कुल जनसंख्या का एक भाग न्यूनतम जीवन स्तर से वंचित रहता है तब देश मे निर्धनता की स्थिति मानी जाती है। जब समाज का एक बहुत बड़ा भाग केवल निर्वाह स्तर पर गुजारा करता है तो कहा जाता है कि समाज में व्यापक निर्धनता विद्यमान है। भारत मे आजादी के समय यही स्थिति थी।

24/02/2020

③ कम मजदूरी :- भारतीय अर्थव्यवस्था इसलिए पिछड़ी हुई थी क्योंकि यहाँ मजदूरी की दरें बहुत कम थी। डा० राधाकमल के अनुसार यहाँ के मजदूरों की वास्तविक मजदूरी दरें अंग्रेजों के नीतियों के फलस्वरूप घट गई थी पर अब स्वतंत्रता मिलने के बाद इसमें कुछ सुधार अवश्य हुआ था परन्तु फिर भी वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बहुत कम थी।

④ भारी जनसंख्या दबाव :-

भारत में पिछड़ी अर्थव्यवस्था होने का मुख्य कारण उच्च जन्म-दर था। जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही थी। उसकी तुलना में रोजगार उद्योग धंधों में कम वृद्धि के कारण बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। बढ़ती हुई जनसंख्या की मौलीक आवश्यकता को पूरा करने का भी दबाव भी अर्थव्यवस्था पर बढ़ता जा रहा था।

Scanned with CamScanner

(5) परंपरागत कृषि :-

भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी अर्थव्यवस्था मानी गयी है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण परंपरागत ढंग से कृषि करना है। आजादी के समय भारत में परंपरागत कृषि होती थी। किसान लकड़ी के हल और बैल से खेत करते और सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर रहते थे तथा साधारण किस्म के बीज का उपयोग करते थे। इसके कारण उत्पादन की मात्रा काफी कम होती थी।

(6) कमजोर औद्योगिक ढांचा :-

भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी होने का एक मुख्य कारण कमजोर औद्योगिक ढांचा भी था। ब्रिटेन की नीतियों के कारण यहाँ के परंपरागत उद्योग नष्ट हो चुके थे, लेकिन साथ ही कुछ नये उद्योगों की स्थापना की शुरूआत हो गयी थी जैसे लोहा, कपड़ा, जूट के मिलों की स्थापना आदि को इस पर व्यापक स्तर पर औद्योगिक करण नहीं कहा जा सकता था।

(7) जनसंख्या का व्यवसायिक आधार पर वितरण :-

भारत में जनसंख्या का व्यवसायिक आधार पर वितरण पाया जाता है। अधिकांश जनसंख्या कृषि व उससे संबंधित कार्यों में लगी है इसलिए इसे पिछड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है।

(4) गतिहीन अर्थव्यवस्था (Stagnant Economics) :-

अर्थ :- गतिहीन अर्थव्यवस्था को ही सुस्त अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। गतिहीन या सुस्त अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय स्थिर रहती है।

Scanned with CamScanner

ऐसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन स्थिर रहता है। औद्योगिक विकास नहीं होता और कृषि का उत्पादन भी स्थिर रहता है।

25/02/2020

आर्थिक गतिहीनता के कारण :-
(Causes of Stagnant Economics) :-

ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीनता और आर्थिक पतन की ~~अर्थव्यवस्था~~ अवस्था से गुजरी थी। इस काल में विश्व के अनेक देश तेजी से आर्थिक विकास पर भारतीय अर्थव्यवस्था गति हीन थी। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे :-

(1) ब्रिटिश सरकार की समान नीतियाँ :- भारत ब्रिटिश सरकार का एक उपनिवेश था। इसका प्रशासन ब्रिटेन से होता था। इसके औद्योगिक विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता था। कृषि व औद्योगिक उत्पादन में ब्रिटिश सरकार पुरानी तकनीक का ही इस्तेमाल करती थी जिसके कारण भारत का औद्योगिक ढांचा और आधारभूत उद्योगों का विकास नहीं होता था।

(2) जनसंख्या में वृद्धि :- (a) जनसंख्या वृद्धि से देश में आर्थिक विकास के क्षेत्र में बड़ी अड़चन पैदा होती है। इससे एक ओर तो पूंजि निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और दूसरी ओर तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए रोजगार तथा उपभोग सामग्री के लिए अधिकाधिक मात्रा में निवेश की आवश्यकता उत्पन्न होती है।

(b) जनसंख्या में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में अधिक

Scanned with CamScanner

वृद्धि होने पर भी प्रति व्यक्ति आय कम ही बढ़ पाती है।

(3) भूमिकर व ~~भूसवामी~~ भू स्वामित्व संबंधी नीति :-

कार्नवॉलिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करके जमींदारों को भूमि का स्वामित्व प्रदान कर दिया। जो किसान जमींदारों को जितना अधिक लगान देता था वही भूमि में खेती कर सकता था। इससे किसानों का शोषण जमींदारों ने प्रारंभ कर दिया। उधर सरकार की लगान बढ़ती चली गयी और यह लगान सरकार की ~~मु~~ आय का मुख्य साधन था।

(4) धार्मिक दृष्टिकोण एवं अभिवृत्तियाँ :-

आर्थिक गतिहीनता के लिए लोगों के धार्मिक दृष्टिकोण भी जिम्मेदार है। भारत में धर्म के प्रभाव के कारण लोग भौतिक वस्तुओं से कम लगाव रखते थे और परलोक संबंधी बातों को अपने जीवन में अधिक महत्व देते थे। अपनी वर्तमान सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर लोग संतोष करते थे और उसमें सुधार लाने का कोई प्रयास भी नहीं करते थे। आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उनमें निवेश संबंधी क्षमता व तत्परता की कमी थी। यह स्थिति अर्थव्यवस्था को गतिहीन बनाती चली गई।

(5) सामाजिक ढाँचा -

गतिहीन अर्थव्यवस्था के लिए जैसे परिवार प्रथा, जाति प्रथा आदि सामाजिक संस्थाओं का विशेष हाथ रहा। अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। संयुक्त परिवार प्रणाली, जाति प्रथा आदि से श्रम व पूंजी की गतिशीलता

Scanned with CamScanner

रूकी, व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता सीमित हो गई। ऊँच नीच और छुआ छूत की भावनाओं को बल मिला तथा आपसी संदेह, कलह, अनावश्यकता को बढ़ावा मिला। इस प्रकार देश के आर्थिक विकास में सामाजिक ढाँचे की ओर से रूकावटें आयी। जिसके कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी रही।

Other Salient features :-

→① विदेशी सरकार की भूमिका तथा नीति :-

विदेशी सरकार ने मुक्त व्यापार नीति को अपनाया जबकि यह नीति भारत के लिए ठीक नहीं थी। फिर भी ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी इस नीति को भारत पर थोप दिया।

② इंगलैण्ड में औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी ऐसे में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की दो प्रमुख आवश्यकता थी :-

(a) कारखानों में तैयार माल की खपत के लिए बाजार
(b) उद्योगों के लिए कच्चे माल तथा बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अनाज

③ इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशी सरकार ने भारत में मुक्त व्यापार की नीति को लागू किया।

④ मशीन का बना सस्ता विदेशी माल बिना किसी रूकावट देश में आने लगा जिसके कारण विश्व विख्यात परंपरागत उद्योग एक-एक करके नष्ट होते गये।

⑤ भारत औद्योगिक देश के स्थान पर एक खेतीहर देश बन गया।

⑥ विदेशी सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को दोषपूर्ण अर्थव्यवस्था का रूप दिया और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था

Scanned with CamScanner

के विकास के लिए इसका शोषण किया।

Conclusion (सारांश):-

① ब्रिटिश काल में आर्थिक गतिहीनता का मूल कारण यह था कि सरकार ने आर्थिक क्षेत्र में अपना आवश्यक योगदान नहीं दिया। अन्य देशों की सरकारें विभिन्न तरीके से आर्थिक विकास में लगी हुई थी वहीं भारत में विदेशी सरकार ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को एक उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का रूप देकर अनेक प्रकार से इसका शोषण कर रही थी।

② इस प्रकार ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन दशा में पड़ी रही जिसके कारण गरीबी और बेरोजगारी की समस्याएँ बढ़ी और समय के साथ-साथ देश के आर्थिक विकास का कार्य जटिल बनता गया।

③ स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा अत्यन्त असंतोषजनक थी। वह अल्पविकसित अवस्था में थी। उसका स्तर नीचा था और आधार कमजोर था। देश में आधुनिक उद्योगों का अभाव था विशेष रूप से आधार मूलक (Infrastructure) का अभाव था। हमारी खेती बहुत पिछड़ी हुई दशा में थी। इस प्रकार आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था के हर अंग पर पिछड़ेपन की गहरी छाप थी।

Scanned with CamScanner

→ Planning Exercise in India :-

National Planning Committee :-

भारत में आयोजन के कर्णधार जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में 1938 राष्ट्रीय आयोजन समिति नियुक्त की गई। इस समिति ने यह मत व्यक्त किया कि :-

(1) समस्त मूल उद्योगों और सेवाओं, खनिज-साधनों, रेल, जलमार्ग, जल परिवहन और अन्य सार्वजनिक उपयोगिता वाले उद्योगों पर राज्य का स्वामित्व या नियंत्रण होना चाहिए।

(2) यह सिद्धांत अन्य बड़े पैमाने के उद्योगों पर भी लागू होना चाहिए जिनमें एकाधिकार कायम होने की संभावना है।

(3) समिति ने यह स्पष्ट कर दिया कि कुटीर उद्योगों और बड़े पैमाने के उद्योगों में कोई विरोध नहीं है।

(4) आर्थिक विकास के लिए अर्थव्यवस्था का औद्योगिकरण आवश्यक है किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि कुटीर उद्योगों की अपेक्षा की जाए।

(5) कृषि का समावेश किए बिना राष्ट्रीय आयोजन कि कोई भी योजना नहीं बनाई जा सकती। इस समिति ने उचित क्षतिपूर्ति देकर जमींदारी प्रथा को समाप्त करने की सिफारिश की।

(6) भूमि के वैयक्तिक स्वामी के अधिक फैलाव को स्वीकार करते हुए सहकारी खेती के स्थान पर खेती करने की सिफारिश की।

Scanned with CamScanner

(7) ऊँची कृषि आय पर आयकर की भाँति एक आरोही कर लगाना ठीक समझा गया।

(8) राष्ट्रीय आयोजन समिति ने 10 वर्ष में जनता का जीवन स्तर दुगना करना अपना लक्ष्य रखा।

→ **Bombay Plan :- (बॉम्बे योजना).**

1944 में राष्ट्रीय आयोजन समिति के अतिरिक्त 8 उद्योगपति ने Mr. J.R.D. Tata, G.D. Birla, Purshottam Das Thakur Das, Lala Shri Ram, Kastur Bhai Lal Bhai, A.D. Shroff, Ardeshir Dalal and John Mathai ने मिलकर भारत के आर्थिक विकास की एक योजना तैयार की जिसे बॉम्बे योजना कहा जाता है।

इस योजना में प्रति व्यक्ति आय को 15 वर्ष में दोगुना करने की और राष्ट्रीय आय को तीन-गुना करने की बात कही गई थी।

लेकिन जवाहर लाल नेहरू ने उसे officially स्वीकार नहीं किया लेकिन कुछ मुद्दों को भविष्य के आयोजन में शामिल किया गया।

→ **Gandhian Plan (गाँधीवादी योजना) :-**

आचार्य श्रीमन नारायन ने जो गाँधी जी के अनुयायी थे उन्होंने गाँधीवादी योजना का उल्लेख किया जिसमें निम्नलिखित मुद्दे थे :-

(1) 10 वर्ष की अवधि में न्यूनतम जीवन स्तर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा।

(2) कृषि और उद्योग के एक साथ एवं संतुलित विकास पर बल दिया।

(3) इस योजना में कुटीर तथा लघु उद्योगों को प्रोत्साहित

Scanned with CamScanner

करने का विशेष रूप से उल्लेख किया गया।

→ People's Plan (जनता योजना) :-

इस योजना का प्रतिपादन विश्व प्रसिद्ध क्रांतिकारी Shri M.N. Rai ने किया। यह योजना रूसी आयोजन के अनुभव से प्रेरित थी। इसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया गया :-

(1) सामूहिक या सरकारी खेती पर बल दिया गया।
(2) भूमि के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश की गई।
(3) उपभोग वस्तु उद्योगों के विकास पर बल दिया क्योंकि इनके विकास द्वारा जनता के जीवन स्तर को शीघ्र उन्नत किया जा सकता था।

Conclusion:-

इन सभी योजनाओं का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि ये सब कागजी योजनाएँ थी जिन्हें क्रियान्वित नहीं होना था लेकिन इन योजनाओं ने भारत में आयोजन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोच को अवश्य प्रोत्साहित किया।

→ The Planning Commission
(योजना आयोग)

भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 March 1950 को हुई जिसके बारे में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्तावना पारित किया।
प्रो० हेन्सन के अनुसार "यह मात्र सलाहकारी संगठन है। योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। अतः इसका संगठन परामर्शदात्री तथा विशेष संस्था के रूप में सरकार के एक प्रलेख (Draft)

Scanned with CamScanner

द्वारा हुआ। योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री ही होता है।

संगठन

↓

अध्यक्ष (P.M.)

↓

उपाध्यक्ष

↓

सदस्य (वित्त) सदस्य (गृह) सदस्य (रक्षा)

नियोजन (आर्थिक संगठन) की एक योजना है जिसमें एक निश्चित समय में सुनिश्चित व सुपरिभाषित लक्ष्यों की प्राप्ती के लिए आर्थिक शक्तियों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है।

नियोजन को अपनाकर सीमित संसाधनों के द्वारा निश्चित समयावधि में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की चेष्टा देश करता है।

विकासशील देश होने के नाते भारत में अपनी कुछ विशिष्ट समस्याएँ हैं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, क्षेत्रीय विकास में असंतुलन तथा असमानता आदि अतः इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1951 से पहले पंचवर्षीय योजना औपचारिक रूप से प्रारंभ हुई। अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएँ बनाई गई हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना को आखिरी योजना कहा जाता है क्योंकि योजना आयोग के स्थान पर अब भारत सरकार ने 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग (Niti Ayog) ("The National Institution for Transforming India) (राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्था) की स्थापना कर दी है। यह संस्था सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम कर रही है। इस संस्था के पहले अध्यक्ष नरेन्द्र मोदी हैं। थिंक टैंक का मतलब होता है विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक समस्याओं पर सलाह देने वाला विशेष समूह।

28/02/2023

Scanned with CamScanner

UNIT- 2

23 2 1996

→ भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना

Structure of Indian Economy

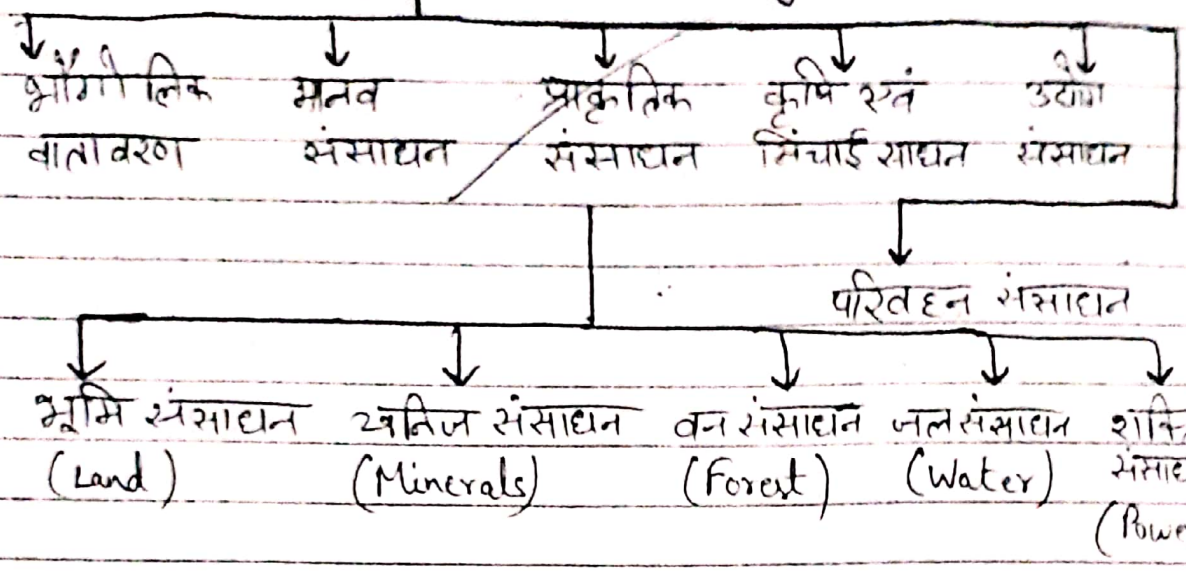

- भौगोलिक वातावरण
- मानव संसाधन
- प्राकृतिक संसाधन
  - भूमि संसाधन (Land)
  - खनिज संसाधन (Minerals)
  - वन संसाधन (Forest)
  - जल संसाधन (Water)
  - शक्ति संसाधन (Power)
- कृषि एवं सिंचाई साधन
- उद्योग संसाधन
- परिवहन संसाधन

① **भौगोलिक वातावरण** – भारत की प्राकृतिक सीमाएँ उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी, दक्षिण में पश्चिम अरब सागर, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, तथा दक्षिण में हिन्द महासागर। इस देश की सीमाएँ उत्तर पूर्वी चीन, नेपाल, भूटान से पूर्व में म्यांमार, बांग्लादेश से उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान से मिलती हैं।

जलवायु की दृष्टि से भारत में विषमताएँ पायी जाती हैं। यहाँ चेरापूंजि के समीप मसीनराम नामक गाँव के स्थान पर अधिक वर्षा होती है। जबकि पश्चिम राजस्थान और कच्छ जैसे स्थानों पर कम वर्षा होती है। इसलिए भारत में अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ पायी जाती हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टीयाँ भी पायी जाती हैं जिससे उनकी उर्वक शक्ति विभिन्न प्रकार की है जो अलग-अलग फसलों के लिए सर्वोत्तम है। भारत की भौगोलिक स्थिति का कृषि, उद्योग व परिवहन पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। भौगोलिक स्थिति के कारण सिंचाई के लिए जल की उपलब्धि नदियों से प्राप्त हो जाती है।

Scanned with CamScanner

(2) मानव संसाधन :- आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों साधनों का उपयोग आवश्यक है। मानवीय साधन प्राकृतिक साधन का उपयोग करते हैं। भारत की जनसंख्या विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत में जनसंख्या का बहुत अधिक भार है तथा भूमि का क्षेत्र बहुत सीमित है।

(3) प्राकृतिक संसाधन :- इन सभी संसाधनों से प्राप्त आशय है प्रकृति से प्राप्त भौतिक संपदाओं या साधनों से है। किसी देश में उपलब्ध होने वाली भूमि, खनिज पदार्थ, जल संपदा, वन संपदा, वर्षा एवं जल वायु भौगोलिक स्थिति तथा प्राकृतिक बंदरगाह उस देश के प्राकृतिक साधन माने जाते हैं। भारत के समुचित प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन निम्नलिखित बिंदुओं में किया जा सकता है :-

① भूमि ③ वन ⑤ शक्ति
② खनिज ④ जल

(4) कृषि एवं सिंचाई संसाधन :- भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश के विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में आर्थिक प्रगति के लिए जो प्रयत्न किए गए उनमें कृषि को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय आय का लगभग 1/3 भाग इसी क्षेत्र से मिलता है। देश में आंतरिक व्यापार में कृषि का बहुत अधिक महत्व है। स्वतंत्रता प्राप्ती के बाद बहुत सी बहुउद्देश्य सिंचाई योजनाएँ शुरू की गई है जैसे भाकरा नंगल डैम, (हिमांचल प्रदेश) (सतलज नदी), दामोदर घाटी, हीराकुड डैम (उड़ीसा) (महानदी)

(5) उद्योग संसाधन :- उद्योग के विकास द्वारा, आय, उत्पादन, रोजगार की मात्रा को बढ़ाकर भारतीय

अर्थव्यवस्था में रफ्तार लायी जा सकती है।
उद्योग में देश की कार्यशील जनसंख्या का 12% लगा हुआ है। सकल्पीय आय में उद्योग का उद्योग का योगदान 27.4% है।
भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा 24जुलाई को लोकसभा में की गई।
यह नीति उदार एवं खुली अर्थव्यवस्था का सूत्रपात करने वाली है। इस नीति का उद्देश्य देश की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में सुधार करना तथा देश के उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाना था।

⑥ परिवहन संसाधन:- किसी देश की आर्थिक व्यवस्था के विकास में परिवहन साधनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। परिवहन साधन कृषि, उद्योग तथा व्यापारिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। रेलवे तथा सड़कों के निर्माण से देश के सभी प्रमुख नगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसके फलस्वरूप औद्योगिक वस्तुओं का आकार बढ़ गया है। भारत में परिवहन साधनों को पाँच भागों में बाँटा गया है:-

① रेल
② सड़क
③ वायु
④ जल

31/3/2020

Scanned with CamScanner